

स्मृति ईरानी होंगी, भाजपा की तरफ से दिल्ली के मु.मंत्री पद की उम्मीदवार

आप द्वारा आतिशी मारलेना को मु.मंत्री बनाने के बाद स्मृति ईरानी का नाम सबसे ऊपर है, भाजपा के मु.मंत्री के चेहरे के रूप में

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 सितम्बर। लोकसभा चुनावों में अमेठी सीट पर किशोरी लाल शर्मा के हाथों पराजित हो जाने और उसके बाद उपेक्षा का दंश झेलने के बाद, अब ऐसी संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आर्क लाइट में वापस आ जायेंगी। दरअसल, पार्टी हाईकमान उन्हें अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रचार अभियान के चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है।

अमेठी की हार के बावजूद, ऐसी आशा की जा रही थी कि हाई प्रोफाइल नेता ईरानी या तो राज्यसभा में समायोजित कर ली जायेगी या फिर उन्हें संगठन के अंदर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी जायेगी। लेकिन ईरानी, अपना सरकारी आवास खाली करने के बाद के महीनों में ब्रेकिंग मोड में हैं। उन्होंने कुछ सप्ताह पहले उस समय जरूर सार्वजनिक क्षेत्र में जरा सा ध्यान आकर्षित किया था, जब उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में अप्रत्यक्ष रूप से

■ एक बार बॉसुरी स्वराज के नाम पर भी चर्चा हुई थी, पर, स्मृति ईरानी के राजनैतिक अनुभव व पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की क्षमता के कारण स्मृति ईरानी को ज्यादा उपयुक्त माना गया।

■ दिल्ली के मु.मंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर पार्टी के नेताओं की दो बैठक वृंदावन व पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित मुख्यालय में हो चुकी हैं, पर, अंतिम निर्णय रणथम्भोर में आयोजित होने वाले वरिष्ठ नेताओं की बैठक में फाइनल होने की बात है।

■ सामान्य तौर पर, भाजपा में चुनाव से पूर्व भावी मु.मंत्री का नाम घोषित करने की परम्परा नहीं है। परन्तु, 2015 में पहली बार किरण बेदी के नाम की घोषणा की थी, जैसे ही किरण बेदी आप छोड़कर भाजपा से जुड़ी थीं। चुनाव से पूर्व, पर, यह परीक्षण बुरी तरह असफल रहा था।

■ न केवल किरण बेदी स्वयं हार्य, आप ने भी प्रचंड बहुमत से 70 में से 67 सीट जीत अपनी सरकार बनायी थी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि जब वे सफेद टी-शर्ट पहने हुये संसद में बैठे थे तो वे युवाओं का ध्यान बरबस ही अपनी ओर

खींच रहे थे। ईरानी ने कहा था कि अब राहुल गांधी के कार्यों और शब्दों में कथनी और करनी में एक रणनीति निहित होती है। ईरानी का यह इन्टरव्यू वायरल हुआ

था और ऐसी अटकलें लगने लगी थीं कि वे मोदी-शाह के राजनैतिक तौर-तरीकों से स्वयं को दूर कर रही हैं तथा आर.एस.एस. के नज़दक जा रही है।

उल्लेखनीय है कि पार्टी महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष, जो आर.एस.एस. से भाजपा में आए हैं, मंगलवार को हुई राजनेताओं की उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें स्मृति ईरानी को दिल्ली में कोई भूमिका देने की चर्चा हो रही थी। भाजपा सामान्यतः मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करती है, लेकिन 2015 में पार्टी इस नीति से हट गई थी तथा उसने किरण बेदी को केजरीवाल की आप को छोड़ने के चन्द रोज के अन्दर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया था। भाजपा के लिये यह प्रयोग बुरी तरह प्लॉप रहा था तथा दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 67 सीटें आप ने जीत ली थीं तथा स्वयं किरण बेदी, कृष्णा नगर सीट पर आप के एस.के. बग्गा से चुनाव हार गई थीं।

आतिशी मारलेना के मुख्यमंत्री बनने के बाद, ईरानी का नाम एक महिला के रूप में, भाजपा की ओर से एक प्रभावी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जैसलमेर के फायरिंग रेंज में मोर्टार बम फटा

जैसलमेर, 20 सितम्बर (निसं)। जैसलमेर जिले की पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास के दौरान ट्रेनी जवानों से मोर्टार बम फटने पर 4 जवान घायल हो गए और 2 को गंभीर हालत में होने पर पोकरण अस्पताल में इलाज के बाद जोधपुर रेफर किया गया है।

जैसलमेर की पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में शुक्रवार दोपहर को बड़ा हादसा हो गया। युद्धाभ्यास के दौरान

■ युद्धाभ्यास के दौरान हुए इस हादसे में चार जवान घायल हो गए तथा दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

एक मोर्टार बम अचानक फट गया। हादसे में सीमा सुरक्षा बल के चार जवान घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर हड़कंध मच गया। सभी घायलों को पोकरण हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बी.एस.एफ. के वरिष्ठ अधिकारी और पोकरण पुलिस अस्पताल हॉस्पिटल पहुंचे। घायल जवानों के नाम उदय, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिन में दी जाए। अगले बुधवार को इस पर सुनवाई होगी।

सोशल मीडिया पर जस्टिस श्रीषानंद के वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में वे बैंगलोर के मुस्लिम बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' कहते नज़र आ रहे हैं तथा दूसरे वीडियो में वे महिला पर 'आंतरिक वस्त्र' सम्बंधी अभद्र टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं।

सोशल मीडिया सक्रिय भूमिका निभाता है, ऐसे में यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि न्यायिक टिप्पणियां गरिमापूर्ण होंगी चाहिए।

सी.जे.आई. ने कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज द्वारा सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी पर हमारा ध्यान गया है हमारा कर्नाटक हाई कोर्ट से आग्रह है कि इस संबंध में रिपोर्ट दें और रिपोर्ट दें

बस खाई में गिरी, बी.एस.एफ. के चार जवान मरे

श्रीनगर, 20 सितंबर। जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में एक बस के खाई में गिरने से सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) के कम से कम चार जवानों की मौत हो गई और 26 घायल हो गये।

अधिकारियों ने बताया कि बी.एस.एफ. द्वारा दूसरे चरण के चुनाव ड्यूटी के लिए किराए पर ली गई एक सिविल

■ जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में यह हादसा हुआ। यह बस चुनाव ड्यूटी के लिये किराये पर ली गयी थी।

बस बडगाम के वतरहाल इलाके के ब्रेल के पास एक खाई में गिर गई, जिसके कारण बीएसएफ के कई जवान घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया, घायलों में से चार की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि करीब 26 घायलों को बडगाम और श्रीनगर में विभिन्न (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सुप्रीम कोर्ट का कोलीजियम कोई सर्च पैनल नहीं है'

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि जवाब दे कि कोलीजियम द्वारा जजों की नियुक्ति के लिये भेजे गये नाम पर अभी तक "नियुक्ति" क्यों नहीं हुई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 सितम्बर। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो संभवतया कार्यपालिका व न्यायपालिका के रिश्ते को प्रभावित कर सकता है, के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आज मोदी सरकार से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए कितने नाम प्रस्तावित किए हैं और सरकार कारण बताए कि अभी तक भी इन पर विचार क्यों नहीं किया गया है और वे किस स्तर पर लम्बित हैं।

तीन जजों की बेंच की अध्यक्षता करते हुए जज डी.वाय. चंद्रचूड़ ने एटॉर्नी जनरल आर. वैकटरमानी से कहा कि आप एक चार्ट लेकर आईए और हमें हरेक सिफारिश, जिसे कोलीजियम ने दोहराया है, का स्तर

बताइए और यह भी बताइए कि उन नियुक्तियों में क्या समस्या है। सी.जे.आई. ने कहा, मिस्टर एटॉर्नी जनरल हमारा आइडिया गुप्त बातें सामने लाने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का है ताकि सरकार का काम चलता रहे, बसा।

बैंच में जस्टिस जे.जी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। बैंच ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए निर्देश दिए जिसमें मांग की गई थी कि कोलीजियम द्वारा अनुशंसित जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी करने की समय सीमा फिक्स की जानी चाहिए।

बैंच ने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम कोई सर्च कमेटी नहीं है, जिसकी सिफारिशों को रोका जा सकता हो।" सी.जे.आई. ने मोदी सरकार की कार्यशैली की कड़ी

■ सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अगर कोलीजियम द्वारा अनुशंसित जिन जजों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, सरकार कारण भी बताये कि उनकी नियुक्ति नहीं करने का कारण क्या है? नियुक्ति देने में क्या दिक्कत है।

■ मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित इस बैंच में दो अन्य सदस्य थे। न्यायाधीश पारदीवाला व न्यायाधीश मनोज मिश्रा। यह बैंच उस जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें मांग की गई है कि न्यायालय वह अवधि निर्धारित करे, जिसमें सरकार कोलीजियम द्वारा नियुक्ति के लिए भेजी गई सिफारिशों पर नियुक्ति दे।

आलोचना की और कहा कि क्या आप कोलीजियम द्वारा दुबारा भेजे गए नामों की लिस्ट बना सकते हैं और बता सकते हैं कि ये नाम किस स्तर पर

लम्बित हैं और क्यों?

बैंच ने कहा कुछ नियुक्तियां होने वाली हैं और हमें उम्मीद है कि ये जल्दी ही होंगी। उसके बाद एटॉर्नी

तिरूपति प्रसादम विवाद के बाद कर्नाटक सरकार भी एक्शन मोड में आई

कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों में वितरित होने वाले प्रसादम की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए हैं

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 सितम्बर। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में तिरुपति लड्डू में कथित मिलावट को लेकर पैदा हुए आक्रोशपूर्ण विवाद के बाद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने स्वाभाविक चिन्ता के फलस्वरूप, राज्य के सभी बड़े मंदिरों में बंटने वाले प्रसादम के जॉच अभियान चलाने के आदेश जारी कर दिए।

प्रसंगवश बता दें कि सुप्रसिद्ध तिरुपति लड्डू, जिस पर जी.आई. टैग है, में अशुद्धता के प्रवेश की बात, घी के सप्लायर के बदलाव के बाद, जानकारी में आई है। पिछले वर्ष जुलाई तक, प्रसादम बनाने के लिए मन्दिर ट्रस्ट को "कर्नाटक मिलक फेडरेशन" नन्दिनी ब्रांड घी की सप्लाई करता था। लेकिन के.एम.एफ. ने घी के दाम बढ़ा दिए, तो अनुबन्ध टूट गया था तथा घी की सप्लाई का ठेका तमिलनाडु के डिंडीगल नामक स्थान पर स्थित "ए.डी.डेयरीज" को दे दिया गया था। गत वर्ष अगस्त से नई व्यवस्था शुरू हो गई थी, उस समय आन्ध्र प्रदेश में वाई.एस.आर.सी. का शासन था।

■ तिरुपति प्रसादम में अशुद्धि तब सामने आई जब घी का सप्लायर बदला गया। गत जुलाई तक प्रसादम के लिए कर्नाटक मिलक फेडरेशन से नन्दिनी घी मंगाया जाता था।

■ पर, कर्नाटक मिलक फेडरेशन द्वारा घी की कीमत बढ़ाए जाने पर टी.टी.डी. ने घी वितरण का ठेका तमिलनाडु की एक डेयरी फर्म को दे दिया। उस समय आंध्र में जगनमोहन की सरकार थी, बस तभी से गड़बड़ी शुरु हुई।

■ कर्नाटक सरकार ने अब सभी मंदिरों में प्रसादम के लिए नन्दिनी घी इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है।

हालाँकि कर्नाटक इस विवाद के दोषारोपण से बच गया है, लेकिन यह कोई भी चीज संयोग पर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि राज्य की ऐसी किसी भी घटना से विपक्षी भाजपा को और बल एवं प्रोत्साहन मिलेगा, जो इस समय विपक्षी वाई.एस.आर.सी.पी. पर जबरदस्त भड़कौ हुई है तथा इसके समर्थकों ने भी सोशल मीडिया पर तमिलनाडु पर दोषारोपण करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि कर्नाटक

सरकार ने कहा है कि वह राज्य के सभी मन्दिर-प्रशासनों को केवल नन्दिनी घी को काम में लेने के निर्देश देगी, जिससे वहाँ भक्तों को बाँटे जाने वाले प्रसादम की सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

कर्नाटक के मन्त्री रामलिंगा रेड्डी ने एक निजी टेलिविजन चैनल को बताया, "तिरुपति विवाद के बाद, हमारे कर्नाटक के मन्दिरों में दिए जाने वाले (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुलिस थाने में पुरुष अफसर ने महिला के कपड़े उतारे

पीड़िता एक सैन्य अफसर की पुत्री तथा एक अन्य सैन्य अफसर की मंगेतर है

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 सितम्बर। ओडिशा में प्रधानमंत्री द्वारा महिला सशक्तिकरण के बारे में बोलने के 72 घंटों के अंदर, एक महिला जो सेना अधिकारी की बेटी है तथा एक सैनिक अधिकारी की मंगेतर है, को रात को घर लौटते समय छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, एक पुरुष पुलिस अधिकारी ने उसको निर्वस्त्र किया और उसके आंतरिक वस्त्र भी उतार दिए तथा उससे ऐसी बातें बोली, जिन्हें सार्वजनिक रूप से बोला नहीं जा सकता।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना का विवरण दिया और पूछा, क्या इस तरह से महिलाएं सुरक्षित हैं और प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुप हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार में बहुत व्यस्त हैं और उनके पास समय नहीं है। श्रीनेत ने कहा, "हमें पता नहीं कि भारत की महिला व बाल विकास मंत्री

■ सेना ने इस घटना पर गंभीर नाराजगी जताई। सेना के शीर्ष अधिकारियों ने ओडिशा के डी.जी.पी. और प्रशासन से बात की है। सेना के अनुसार सेवारत सैन्य अधिकारी को हिरासत में लेना और निकटतम सैन्य इकाई को सूचित नहीं करना गैर कानूनी है।

■ कांग्रेस ने इस घटना को लेकर महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, प्र.मन्त्री ने ओडिशा में महिला सशक्तिकरण पर बात की और मात्र 72 घंटे के भीतर ही पुलिस थाने में एक महिला का यौन उत्पीड़न किया जाता है।

कौन है, क्योंकि वो कभी-कभार ही बोलती हैं, वास्तव में तो वो बोलती ही नहीं हैं। भाजपा की महिला सांसदों के लिए संसद में चुना जाना महत्वपूर्ण है, बजाय महिला सुरक्षा तथा सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर अपना मुँह खोलने को।

श्रीनेत ने कहा, "भारत में महिला आयोग भाजपा के मुखपत्र के समान है। लेकिन यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है, इसे कैसे बर्दाश्त किया

जाएगा, इसे कौन उचित ठहरा सकता है? यह किसी ऐसी महिला के साथ नहीं हो रहा है जो शिक्षित नहीं है, जिसे अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। वह एक वकील है। उसकी सगाई सिख रैजिमेंट के एक सेना अधिकारी के साथ हुई है। और यही नहीं, मणिपुर में कारगिल योद्धा की पत्नी के साथ ऐसा हुआ है। मध्यप्रदेश में हमारे सैनिक अधिकारियों की महिला साथियों के

साथ ऐसा हुआ, इस देश में यह क्या हो रहा है? महिलाएं कहीं पर सुरक्षित हैं? पुलिस स्टेशन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जैसा इस केस में हुआ। उस महिला के विरुद्ध अपराध, उसका यौन शोषण, पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ, और इसके लिए जवाबदेह कौन है?"

इस घटना पर कार्यवाही को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में श्रीनेत ने कहा, "सबसे पहला कदम तो यह है कि, यह स्वीकार करना कि उस महिला के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हुआ? उसके साथ क्या-क्या हुआ? कम से कम यह स्वीकार तो करिए। यह भी स्वीकार करिए कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध अनियंत्रित रूप से बढ़ रहे हैं। यही वास्तविकता है। यह हमारी पहली मांग है, इसे छुड़ाए नहीं, यह ढोंग मत करिए कि इस देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि ऐसा है नहीं। यदि वो खेत में काम करने वाली श्रमिक है, तो वो सुरक्षित नहीं हैं, यदि वो हॉस्पिटल में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट का यू-ट्यूब चैनल हैक हुआ

नयी दिल्ली, 20 सितंबर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक कर लिया गया है। पहले जहाँ इस चैनल पर सुप्रीम कोर्ट से जुड़े वीडियो आते थे, वहीं, अब पूरे चैनल पर क्रिप्टोकॉर्सी से जुड़े वीडियो सामने आ रहे हैं।

शीर्ष अदालत संवैधानिक पीठों के

■ सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले चैनल पर क्रिप्टोकॉर्सी से जुड़े वीडियो चले।

समक्ष सूचीबद्ध मामलों और जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई स्ट्रीम करने के लिए यूट्यूब का उपयोग कर रही है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वीडियोज को हैकर्स ने प्राइवेट कर दिया है। बार एंड बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन फिलहाल यूट्यूब चैनल की हैकिंग की जांच कर रहा है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)